झारखण्ड सरकार

Social audit of Pradhanmantri Awas Yojna (Urban) in Jharkhand

"A step towards establishing transparency and accountability"

Background:

Urban Mission is being systematically monitored by Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation which has evolved mechanisms for monitoring and social audit has been mentioned as one of such processes. Mission intends to provide assistance to State/UT Governments in carrying out social audits through credible institutions for ensuring better implementation, accountability, transparency and participation in Pradhanmantri Awas Yojna (PMAY) Housing for All (HFA).

Taking this forward, the Directorate of Urban Administration of Urban Development and Housing Department Govt. of Jharkhand initiated the social audit process by conducting pilot social audit through Social Audit Unit, Department of Rural Development, Govt. of Jharkhand.

The Process:

The key features of pilot social audits are:

- Initially 7 cities selected for social audit (Ranchi, Chas, Deoghar, Mango, Medininagar, Koderma and Sahibganj)
- 1500 DUs have been selected for social audit under BLC projects of 2015-16 and 2016-17

Door to Door Verification

Social Audit Public Hearing at Jamsehdpur

- **Independent Facilitating Agency : "Social Audit Unit"** Rural Development Department, Govt. of Jharkhand
- Beneficiaries were selected by Random Computerized System under selected wards.

Orientation of Officials

- State level orientation training programme was organised at State Institute of Rural Development, Ranchi.
- City level orientation meetings with senior ULB officials conducted at 7 ULBs
- Constituted the Social Audit Committees
- Verification and validation of data, BLC files and payments at ULB Level.
- Interaction and interview of officials, beneficiaries and ward councilors
- Public Hearings were conducted to present the findings of the social audit in 6 ULBs.
- State Level Social Audit Hearing is proposed in December.

Verification with Beneficiary

Social Audit Public Hearing at Sahebganj

Social Audit Orientation at Ranchi

New Paper Coverage of Social Audit

आवासों के सोशल ऑडिट की प्रक्रिया शुरू

संवाददाता

मेदिनीनगर : प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों के सोशल ऑडिट की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर वित्तीय वर्ष 2015 ,16 और 2016 ,17 में बने आवासों का सामाजिक अंकेक्षण किया जाना है। सोशल ऑडिट के तहत नगर निगम को जी पायलट सोशल ऑडिट के रूप में चयनित किया गया है । इसके तहत 200 घरों को चिन्हित कर सोशल ऑडिट टीम द्वारा सामाजिक अंकेक्षण किया जायेगा। सोमवार को सोशल ऑडिट टीम का गठन मेदिनीनगर के सामाजिक लोगों व आम लोगों के साथ किया गया। नगर निगम सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता राज्य स्तरीय सोशल ऑडिट टीम के सदस्य वशिष्ठ नारायण उरांव ने की। बैठक में विभिन्न क्षेत्रों से सामाजिक कार्यकर्ता व एनजीओ के प्रतिनिधि व स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं उपस्थित थे । सामाजिक समिति के सदस्य सोशल ऑडिट टीम को ऑडिट के समय मदद करेंगे । बैठक में सिटी मैनेजर मो आशीफ रिजवीए बीस सूत्री सदर उपाध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ताए राजेश विश्वकर्माए मां संस्था की पुनम विश्वकर्माए इप्टा से रविशंकरए सामाजिक कार्यकर्ता मनोहर कुमारए जेसीएम छात्र संगठन से राहित कुमार सिंह ए मुन्ना सिंह ए इसडो के महासचिव पंकज लोचनए सिटी इंजीनियर मनोरंजन सिंह समेत कई लोग मौजूद थे।

नगर निगम में बैठक

प्रधानमंत्री आवास योजना का होगा सोशल ऑडिट

नगर निगम की बैठक में वार्ड पार्षद .

संवाददाता ▷ देवघर

- ग्रामीण विकास विभाग करा रहा ऑडिट
- आवास जाकर लाभुकों की जानेगी परेशानी
- एक से पांच तक चलेगा ऑडिट

प्रभात खबर Mon, 29 October 2018 epaper.prabhatkhabar.com/c/3350

पीएम आवास योजना के तहत जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन

जन सुनवाई में उप महापौर, कार्यपालक पदाधिकारी व अन्य।

डालटनगंज, 1 दिसंबर (थर्ड आई) : प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के समा. जिक अंकेक्षण के तहत आज नगर निगम के सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन सुनवाई कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गयी। इस दौरान पूर्व में आवास योजना के तहत स्वीकृत लाभुकों को निगम द्वारा क्या लाभ दिया गया है। वार्ड पार्षदों से जानकारी मांगी गयी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र में आवास योजना के लाभ लेने वाले लाभुकों को निशुल्क गैस, पानी और बिजली का कनेक्शन दिया जाना है। लेकिन शहरी क्षेत्र के किसी भी लाभुकों को यह लाभ नहीं दिया गया। इसी तरह आवास योजना के नियम के तहत सरकार द्वारा निर्धारित राशि से अगर लाभुक आवास बनाने में सक्षम नहीं है, तो उसके लिए बैंक से चार प्रतिशत दर पर लोन देने का भी प्रावधान है। इस मामले में भी लाभुकों को जानकारी नहीं दिया गया, जिससे लाभुकों को अपने घर से पैसा लगाकर आवास का निर्माण करना पड़ा है। जन सुनवाई कार्यक्रम में यह बात उभकर सामने आयी कि आवास योजना का व्यापक तौर पर सही तरीके से जानकारी नहीं दी गयी है। जन सुनवाई में उप महापौर मंगल सिंह, नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी अजय राय, संवाद प्रतिनिधि विजय ओझा, विधायक प्रतिनिधि राजकुमार गुप्ता (रिटायर्ड गुप्ता), प्रभाज 20 सूत्री अध्यक्ष सुशील सिंह, 20 सूत्री सदस्य राजेश गुप्ता, राजेश विश्वकर्मा, मिथलेश कुमार, अशोक कुमार सिंह, विवे, कानंद त्रिपाठी, राजू, राम, हीरामणि तिर्की, इंद्रदेव राम, ऑडिटर सुनील कुमार तिवारी, विशिष्ट नारायण राव सहित सभी वार्ड पार्षद उपस्थित थे।

चास एक्टिविटी prabhatkhabar.com लाइफ संडे बोकारो

नगर निगम. सामाजिक अंकेक्षण के बाद हुई जनसुनवाई, अधिकारियों ने दिया निर्देश

एजेंसी व दोषी कर्मियों पर करें कार्रवाई

कामों में अपूर्ण कार्य को दिखा दिया पूर्ण

Sample of Analytical Reports used for Policy Decisions

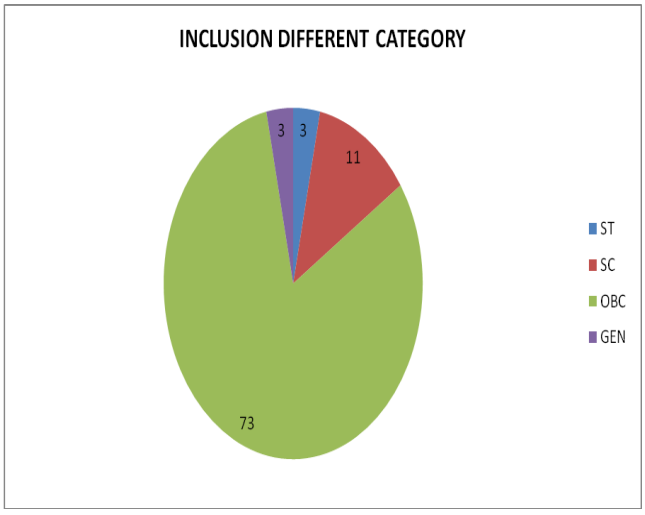

*Report from Sahebganj District

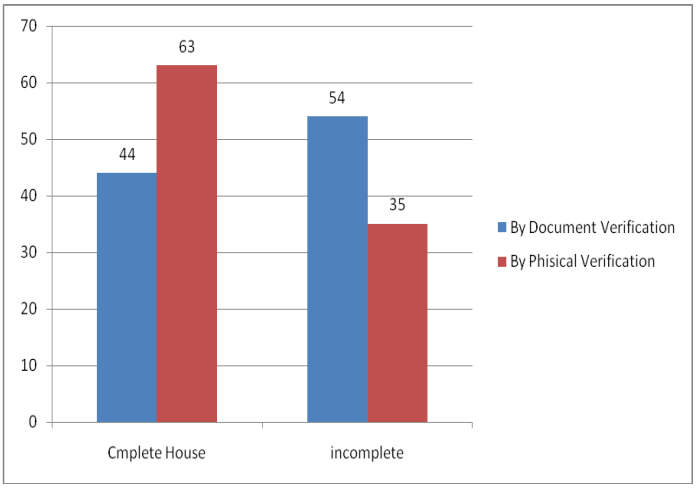

*Report from Mango, ULB

About Social Audit Unit

Social audit is a democratic process that ensures public accountability of agencies through a systematic demand of information by the community. This is in response to the works/programmes that have already been implemented by the government or other agencies for that particular area/community. Within its ambit, it covers issues of quality of implementation of the Programme along with audit of expenses and decisions. It is an empowering process for the people to participate in the process planning and implementation of works and make the implementing agency accountable for the same. Thus it ensures participation, helps maintain transparency and culminates in accountability. In a social audit, the people and the Government jointly monitor the project. It brings on board the perceptions and knowledge of the people, involves them in the task of verification and also brings about much greater acceptability of the government.

After the enactment of the MGNREGA, social audits became a statutory requirement to be conducted by government on a periodic basis. To promote transparency and effective implementation of schemes, the State Government of Jharkhand has established an independent cell Social Audit Unit, Jharkhand within JSLPS for smooth conduct of social audit of MGNREGA and other flagship programmes.

"Truth is the greatest national possession. A state people and a system that suppresses truth or fears to publish it, deserves to collapse"

-Kurt Eisner